फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 71 संख्याः 204 प्रभात जयपुर, मंगलवार 23 फरवरी, 2021 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 10 मूल्य 2.00 रु.

ARBiT TODAY

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

Brajbhumi: The Land of Leela

Krishna showed his divine touch and said "Ladies if no one will accept you; then I will accept all of you and ask you to join me. Will you accept me?"

Triggers of Creativity

J'adore: Colour of the Year

तंजानिया में मादा जिराफ ज्यादा जीवित रहती हैं बशर्ते वे अपना समय मादाओं के बड़े समूह के साथ बिताएं। यह जानकारी मिली है युनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिक के एक शोध में। भोजन की सुलभता, इंसानी दखलंदाजी, व अन्य कारणों की तुलना में उनके जीवित रहने की दर पर मित्रता का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि मादाएं भोजन के स्रोत के बारे में सूचनाओं का आदान- प्रदान करती हैं और बच्चों की देखभाल में एक दूसरे की मदद करती हैं। यही नहीं, अन्य मादाओं के साथ रहने से नर जिराफ द्वारा परेशान किए जाने की संभावना भी कम हो जाती है, तनाव कम होते हैं और मादाएं ज्यादा स्वस्थ रहती हैं। शोधकर्ताओं ने एक दशक तक तंजानिया में मसाई जिराफ का अध्ययन किया, जो कि जिराफ की सबसे बड़ी उपप्रजाति है तथा ये धरती के सबसे ऊंचे कद के जंतु भी हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा जिराफ अध्ययन है। मसाई जिराफ की आबादी हाल ही के दशकों में 50 प्रतिशत तक कम हुई है इसलिए इंटरनैशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर ने इन्हें संकटग्रस्त करार दिया है। इनमें भी वयस्क मादा जिराफ के बीमार, कुपोषित व तनावग्रस्त होने का खतरा ज्यादा होता है। ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। युनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिक में एनिमल बिहेवियर की प्रोफेसर बारबरा कोनिग ने कहा कि, सामाजिक सम्बंध, विचरण की क्षमता बढ़ा सकते हैं तथा ये प्रतिस्पर्धा, परभक्षी जानवरों के खतरे, बीमारी की संभावना और तनाव से निपटने में भी सहायक होते हैं। संभावना है कि मादा जिराफ अन्य मादाओं को बताती हैं कि कहां पर बढ़िया भोजन मिलेगा। यही नहीं, समूह में उन्हें बच्चों की देखभाल में भी सहायता मिलती है। जन्म के बाद एक माह तक तो बच्चे मां के चिपके रहते हैं उसके बाद बच्चों के समूह में शामिल हो जाते हैं। पूरे एक साल तक एक ''बेबी सिटर'' मादा इनकी देखभाल करती है। मादाओं के बीच गहरे सम्बंध होने के कारण बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रायः बच्चे ही परभक्षी जानवरों के निशाने पर होते हैं और आधे से ज्यादा परभक्षी का शिकार बन जाते हैं। एक वाइल्ड लाइफ बायॉलजिस्ट, मोनिका बॉण्ड ने कहा कि जिराफ की सामाजिक आदतें आश्चर्यजनक रुप से इंसानों व अन्य वानरों जैसी होती हैं। ऐसा लगता है कि मादा जिराफ को अन्य मादाओं के साथ मिलजुल कर रहने में ज्यादा लाभ होता है।

राहुल गांधी के दौरे में जो कुछ हुआ, उसके बाद अब राजस्थान कांग्रेस के आंतरिक हालात सुधारने के प्रयास

19 कांग्रेस विधायकों की अयोग्यता के मामले में दायर एस.एल.पी. वापस लेगी राजस्थान सरकार

- मुख्य सचेतक ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया।
- उप चुनाव से पहले, प्रभारी अजय माकन के निर्देश के बाद शुरू हुई एस. एल. पी. वापस लेने की प्रक्रिया।

जयपुर, 22 फरवरी (का.प्र.)। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के 24 जुलाई 2020 के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की तैयारी शुरु कर दी है। मुख्य सचेतक के एडवोकेट इसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ही मुख्य सचेतक की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित अन्य एमएलए व केन्द्र सरकार से जवाब देने के लिए कहा था।

मुख्य सचेतक ने एसएलपी में हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें विधानसभा स्पीकर द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित उनके गुट के कांग्रेस के बागी 19 एमएलए को 14 जुलाई को दिए गए अयोग्यता नोटिस आदेश की क्रियांविति पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था।

बताया जाता है कि दिल्ली से बने दबाव के चलते अब राजस्थान सरकार को इस मामले में यह कदम उठाना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस के अंदर चले आंतरिक विरोध और खेमेबाजी के दौरान जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे की ओर से बाड़ेबंदी का दौर चल रहा था। उसी दौरान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी की ओर से 19 विधायकों को नोटिस जारी किये गए थे। नोटिस जारी किए जाने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट के नजदीकी विधायक पी आर मीणा की ओर से चैलेंज किया गया था और उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए थे।

राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और सरकार की ओर से मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करते हुए 19 विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला उठाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। इस बीच राजस्थान में बदले राजनीतिक हालातों और दोनों खेमों की ओर से चल रही खींचतान को पार्टी के लिए नुकसानदायक मानते हुए प्रभारी अजय माकन ने पार्टी आलाकमान के सामने सारी स्थिति रखी थी। वहीं इन दिनों जिस तरह से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी नेता राहुल गांधी के किसान आंदोलन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और उन आयोजनों में विशाल भीड़ उमड़ रही है, इसका संदेश भी प्रभारी अजय माकन के जरिए आलाकमान तक पहुंचा है। इसी के बाद यह निर्देश दिल्ली की ओर से दिए गए हैं कि वह खेमेबाजी और आपसी तनाव की स्थिति को जितनी जल्दी हो सके खत्म करें, ताकि इसका असर आने वाले दिनों में 4 विधानसभा उपचुनाव पर नहीं पड़े।

आलाकमान को फीडबैक मिल रहा था कि यदि पार्टी में खेमेबाजी रहती है तो इसका असर उपचुनाव पर पड़ेगा और यह संदेश मतदाताओं पर गलत असर डाल सकता है और इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि राज्य सरकार की ओर से एसएलपी वापस लेने के लिए मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है।

जानकारों का कहना है कि पिछले दिनों राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा के दौरान जिस तरह से सरकार और कांग्रेस संगठन की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ जो रवैया अपनाया गया था। उस पूरे रवैये को राहुल गांधी ने नोटिस किया और भले ही यहां उन्होंने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन दिल्ली जाकर पूरी वस्तु स्थिति पर प्रभारी अजय माकन के साथ में चर्चा की। इस चर्चा के बाद मिले निर्देशों के अनुसार ही प्रभारी माकन ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

माकन चार दिन के दौरे पर राजस्थान आएंगे

- रेणु मित्तल-
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 फरवरी। राजस्थान में कांग्रेस के ए.आई.सी.सी. प्रभारी महासचिव अजय माकन 24 से 27 फरवरी तक प्रदेश के चार दिवसीय दौरे पर रहेंगे।

- 24 तारीख को जैसलमेर में मरु मेले का उद्घाटन करेंगे।
- 25 फरवरी को माकन रामदेवरा मंदिर जायेंगे। 26 को जयपुर आयेंगे तथा 27 फरवरी को पार्टी उप चुनावों के लिए अभियान का शुभारंभ करेंगे चित्तौडगढ़ से।

वे 24 फरवरी को जैसलमेर में होंगे जहां वे मरू महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और 25 को वे बाबा रामदेव मंदिर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाबा रामदेव की ''कोरोनिल'' ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को संकट में डाला

इंडियन मैडिकल एसोसियेशन ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को कठघरे में खड़ा किया ''कोरोनिल'' को ''प्रमोट'' करने के कारण

- श्रीनंद झा-
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 फरवरी। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन विवादों में घिर गए हैं, डॉक्टरों की एक संस्था इंडियन मैडिकल एसोसियेशन ने उनके द्वारा कोविड-19 के लिए निर्मित ''वंडर ड्रग'' जिसका नाम ''कोरोनिल'' है, का समर्थन करने के बाबत से स्पष्टीकरण मांगा है। इस दवा को बाबा रामदेव के द्वारा संचालित 'पतंजलि' समूह ने पिछले सप्ताह लांच किया था।

सोशल मीडिया पर सख्त शब्दों वाले एक बयान में आई.एम.ए. ने हर्षवर्धन से प्रश्न किया है कि आप स्वयं एक डॉक्टर हैं तथा एक स्वास्थ्य मंत्री भी है उसके बावजूद आप एक फर्जी व अवैज्ञानिकपूर्ण दवा का समर्थन कैसे कर सकते हैं? आई.एम.ए. एक कॉर्पोरेट घराने के द्वारा उत्पादित दवा का प्रचार करने में पार्टी नहीं बन सकती है। संगठन ने यह भी कहा कि इस कारोबारी का उद्देश्य ''आयुर्वेदिक औषधि'' के नाम पर बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना है, साथ ही यह भी कहा कि ऐसे प्रयास नैतिक रूप से गलत हैं।

- आई. एम. ए ने सोशल मीडिया के मार्फत पूछा कि, स्वयं एक डॉक्टर होते हुए और स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए वे एक ''अप्रमाणित व फर्जी'' दवा को कैसे समर्थन दे सकते हैं।
- डब्ल्यु. एच. ओ. ने भी स्पष्टीकरण दिया कि उसने किसी भी देशी दवा को कोविड-19 के इलाज के रुप में प्रमाणित नहीं किया है।

आई.एम.ए. ने यह भी कहा कि वह मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के घोर दुरूपयोग के खिलाफ नैशनल मैडिकल कमिशन को शिकायत करेगा।

बाबा रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में पिछले सप्ताह इस कोरोनिल औषधि को बाजार में बेचने के लिए उतारा था और इस बारे में दावा किया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर उन्होंने आयुष मंत्रालय से भी कोरोनिल के बारे में मंजूरी प्राप्त कर ली है।

19 फरवरी को डब्ल्यु.एच.ओ. ने एक ट्वीट करके स्पष्टीकरण दिया कि उसने कोविड-19 के ईलाज में उपयोग के लिए किसी भी परम्परागत दवा को उसके असर के लिए प्रमाणित नहीं किया है और न ही उसकी कोई समीक्षा की है।

संयोगवश कोरोनिल इस दावे के साथ बेची जा रही है कि यह एक सहायक दवा है। पतंजलि समूह को खुद आशंका है कि कोई विवाद उठ सकता है? दवा बाजार में आने के बाद से ही बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ट्विटर पर यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि इस दवा को आयुष मंत्रालय से मान्यता मिल गई है जो कि डब्ल्यु.एच.ओ. की मान्यता के समकक्ष है।

डब्ल्यु.एच.ओ. किसी भी दवा को स्वीकार या खारिज नहीं करता बल्कि वह तो पूरे विश्व के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करता है।

ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी

चूरू, 22 फरवरी (का. सं.)। तारानगर-सरदारशहर मार्ग पर बुचावास के पास रविवार शाम करीब 5.30 बजे ट्रक की टक्कर से पिकअप में सवार 3 महिलाओं सहित 5 जनों की मौत हो गई।

पिकअप में सवार एक दर्जन से अधिक अन्य लोग घायल हो गये। पिकअप में राजस्थान के 4 लोगों के अलावा अन्य सभी 15 लोग हरियाणा के थे। एसपी नारायण टोगस ने बताया

- पिकअप में सवार तीन महिलाओं की मृत्यु।

कि ट्रक के गलत साइड से आकर पिकअप को टक्कर मारने से हादसा हुआ। घायलों को देर शाम राजकीय डीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से देर रात सात जनों को गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया गया। सूचना मिलते ही जिला कलैक्टर व पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे में कलावती उम्र (60), भतेरी पत्नी शेरसिंह (60) व सोनू पुत्र सूरजभान

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की तबीयत बिगड़ी

गुर्जर नेता इलाज के लिए जयपुर रैफर

हिण्डौन सिटी, 22 फरवरी (का.सं.)। गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लम्बी लड़ाई लड़ने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की सोमवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें राजकीय अस्पताल की आइसीयू युनिट में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर कर दिया गया।

पीएमओ डॉ. नमोनारायण मीणा ने बताया कि परिजनों के अनुसार कर्नल किरोड़ी बैंसला अपने वर्धमान नगर स्थित आवास पर सोमवार दोपहर आराम कर रहे थे। वे लेटकर खजूर खा रहे थे कि अचानक सांस नली में खजूर का छिलका फंस गया। इससे उनको सांस लेने में परेशानी होने लगी। इस दौरान कैप्टन हरप्रसाद तंवर, जीतू गुर्जर व उनके परिजनों ने उन्हें शहर के मोहन नगर स्थित राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया और इमरजेंसी वार्ड से चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल की आईसीयू यूनिट में भर्ती किया, जहां चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय गुप्ता, डॉ. जल सिंह खटाना व डॉ. अजय शर्मा की टीम ने उनका इलाज शुरू किया।

पिंकी मीणा

जयपुर, 22 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से दस लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रही निलंबित आरएएस पिंकी मीणा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने आरोपी पिंकी मीणा को आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करने की छूट दी है।

पिंकी मीणा की ओर से कहा गया कि उसने न तो रिश्वत राशि की मांग की है और ना ही उसके कब्जे से रिश्वत राशि की बरामदगी हुई है। इसके अलावा एसीबी के पास याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं हैं। उसे प्रकरण में फंसाया गया है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

- जमानत की अर्जी खारिज।

इसका विरोध करते हुए एएजी विभूति भूषण शर्मा ने कहा कि एसीबी के पास आरोपी के रिश्वत मांगने की रिकॉर्डिंग है। प्रकरण में फिलहाल अनुसंधान चल रहा है। यदि उसे जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकती है। वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से मामले में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत अर्जी पेश करने की छूट मांगते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी गई। इस पर अदालत ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आज भाजपा की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक

जयपुर, 22 फरवरी (कासं)। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक संपन्न होने के साथ ही प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन मंगलवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर होगा।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कोर कमेटी के सभी सदस्यों के साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के भी

- क्या वसुंधरा राजे इस बैठक में भाग लेंगी?

मौजूद रहने की पूरी संभावना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कोर कमेटी की सदस्य हैं लेकिन अभी तक कोर कमेटी की एक ही बैठक हुई है और इसमें भी वसुंधरा राजे शामिल नहीं हो सकी थीं। ऐसे में विधानसभा में बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले हो रही बैठक को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

किसान आंदोलन दो राहे पर

किसान यूनियनें व सरकार नयी रणनीति बनाने को मजबूर

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 फरवरी। किसानों का तीन महीने से अधिक समय से चल रहा विरोध प्रदर्शन दोराहे पर आ गया है, क्योंकि इस आंदोलन को नई चुनौतियां मिलनी शुरू हो गइ हैं तथा मोदी सरकार और आंदोलन के नेता, दोनों ही अपनी-अपनी पुरानी रणनीतियों में समायोजन और संशोधन कर रहे हैं।

इस आंदोलन के बेजान हो जाने और किसान नेताओं के बीच बढ़ते मतभेदों को लेकर आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के बीच तीनों विवादास्पद कृषि विधेयकों को रद्द करवाने में इस आंदोलन की संभावित सफलता को लेकर कई प्रश्न उठ रहे हैं।

इस आंदोलन के प्रति मोदी सरकार अपनी इस पुरानी रणनीति पर कायम है कि किसानों की मुख्य मांगों को स्वीकार ना कर उन्हें थका दिया जाए और साथ ही साथ आंदोलन को बदनाम कर इसे पटरी से उतारा जाए। सरकार ने अपने सांसदों, विधायकों व अन्य नेताओं, विधायकों व अन्य नेताओं से कहा है कि वे अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों में किसानों से सम्पर्क साधें।

- सरकार किसी हद तक सफल रही, दिल्ली की सीमा पर आंदोलनकारियों की संख्या घटने लगी है।
- परिवर्तित स्थिति में आंदोलनकारियों के नेताओं ने भी दिल्ली सीमा से ध्यान हटाकर अन्य राज्यों की ओर निगाह की है। यह रणनीति कामयाब हुई पंजाब में, जहां भाजपा को स्थानीय निकाय के चुनावों में बहुत खराब नतीजों का सामना करना पड़ा।
- इसी रणनीति के तहत किसान नेता उन इलाकों में जा रहे हैं, जहां भविष्य में चुनाव निकट हैं। जैसे वैस्टर्न यू.पी., जहां जिला परिषद के चुनाव शीघ्र ही प्रस्तावित हैं।
- भाजपा ने भी आंदोलनकारियों की नयी रणनीति भापते हुए सांसदों व विधायकों को कृषि कानून के मुद्दे को समझाने के लिए किसानों के बीच भेजना शुरु किया है, वैस्टर्न यू.पी. में। पिछले जिला परिषद के चुनाव में भाजपा ने यहां 26 में से पच्चीस जिला पंचायतों पर जीत हासिल की थी।
- इस बार वैस्टर्न यू. पी. में ऐसी सफलता मिलना असंभव सा लग रहा है। भाजपा के सांसद व मंत्री, संजीव बालयान व बुलढाणा के विधायक उमेश मलिक को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु सरकार की, आंदोलनकारियों में मतभेद व शक व शुबहा पैदा करने व देश विरोधी ताकतों, जैसे खालिस्तानियों के साथ सहयोग करने का आरोप कुछ रंगत दिखाने लगा है।

दूसरी ओर किसान यूनियन नेताओं ने भी निर्णय लिया है कि विरोध स्थल दिल्ली की सीमाओं से दूर अलग-अलग राज्यों में हों। इन स्थलों पर अब रैलियां निकाली जा रही हैं। किसान नेताओं ने अब यह अनुभव कर लिया है कि मोदी सरकार उनकी मुख्य मांगों को स्वीकार नहीं करेगी तथा वह अपने निर्णय में विलम्ब कर उन्हें थका रही है जिससे उनका आंदोलन कमजोर पड़ जाए। अतः दिल्ली की सीमाओं पर एक उल्लेखनीय उपस्थिति के जरिए ना केवल निगरानी रखना जरूरी है बल्कि भाजपा के घमंड को चूर करने के लिए उसे चुनावों में भी सबक सिखाना जरूरी है।

इस रणनीति ने पंजाब के स्थानीय निकाय चुनावों में अपना काम किया और किसानों का फोकस अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है जहां जल्दी ही चुनाव होने जा रहे हैं। यहां भाजपा समर्थित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)